अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 105 | श्री विजय पुरम, सोमवार, 20 अप्रैल 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल प्रतिभागियों में से लगभग एक तिहाई महिलाएं हैं; नए भारत में महानगरों से अलग व्यापक भागीदारी सामने आ रही है– केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सिविल सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि उनकी हिस्सेदारी अब 31 प्रतिशत से अधिक हो गई है और कुल सफल उम्मीदवारों के एक तिहाई की ओर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समान अवसर प्रदान करने के कारण अवसरों की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।

शेयर इंडिया स्माइल फाउंडेशन द्वारा अपनी मिशन आईएएस पहल के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2025 के सफल प्रतिभागियों के लिए आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवाओं की बदलती लैंगिक संरचना भारत के विकसित होते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के सबसे उत्साहजनक संकेतकों में से एक है। उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक पहले, सफल प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत थी, जबकि अब यह 30 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जो एक निर्णायक परिवर्तन का संकेत है।

नवीनतम सिविल सेवा परीक्षा– 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 958 अनुशंसित उम्मीदवारों में से 299 महिलाएं हैं, जो कुल का 31 प्रतिशत से अधिक हैं। केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह निरंतर वृद्धि न केवल युवा महिलाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में संसाधनों, सूचनाओं और अवसरों तक बेहतर पहुंच को भी दर्शाती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा अब चुनिंदा अभिजात वर्ग या सीमित भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के उम्मीदवार विविध पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं, जिनमें दूर–दराज़ और वंचित क्षेत्र भी शामिल हैं, और

अल्पसंख्यक कार्य तथा मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस

श्री विजय पुरम, 19 अप्रैल।

अल्पसंख्यक कार्य तथा मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने आज श्री विजय पुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को विस्तार से बताया। उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े हालिया विधायी प्रयासों को विपक्ष से अपेक्षित समर्थन न मिलने पर भी चिंता व्यक्त की।

मंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं को उनका उचित अधिकार देना कोई कृपा नहीं, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है, जिसे सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।

महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अभियान के नाम से जाना जाता है और जिसे आधिकारिक रूप से संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाता है,

के बारे में उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद किए गए अन्य संबंधित विधायी प्रयासों को विपक्षी दलों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाया है।

मंत्री ने परिसीमन की आवश्यकता और महत्व पर भी

शेष पृष्ठ 4 पर

प्रदर्शनी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय फूड फेस्टिवल का सफल समापन

श्री विजय पुरम, 19 अप्रैल

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदर्शनी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय फूड फेस्टिवल का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस उत्सव में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और द्वीपों की समृद्ध पाक–विविधता का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया गया।

यह आयोजन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं व्यापक सहभागिता के साथ प्रारंभ हुआ था। पिछले तीन दिनों के दौरान स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम में पारंपरिक व्यंजनों, विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय पकवानों तथा लोकप्रिय स्ट्रीट फूड से सुसज्जित अनेक खाद्य स्टॉल लगाए गए, जिन्होंने पूरे आयोजन के दौरान भोजन प्रेमियों को आकर्षित किया गया।

आगंतुकों ने विभिन्न विशेष व्यंजनों के साथ–साथ कॉन्टिनेंटल एवं फ्यूजन व्यंजनों का भी आनंद लिया, जिससे यह फेस्टिवल वास्तव में एक स्वादिष्ट अनुभव बन गया। इस आयोजन ने स्थानीय शेफ, स्वयं सहायता समूहों एवं लघु उद्यमियों को अपनी पाक–कला का प्रदर्शन करने तथा स्थानीय स्वादों को बढ़ावा देने के

लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया गया।

उत्सव के माहौल को और जीवंत बनाने के लिए प्रतिदिन सायंकाल लाइव कुकिंग डेमोंस्ट्रेशन, संगीत कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

इस बीच, फेस्टिवल के अंतर्गत स्थल पर एक शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

शेष पृष्ठ 4 पर

14वीं अंतर–ग्राम होड़ी दौड़ (कैनो रेस) चैम्पियनशिप 2026 आयोजित

मुख्य सचिव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

कार निकोबार, 18 अप्रैल

जनजातीय सांस्कृतिक खेलों के अंतर्गत पारंपरिक 16वीं अंतर–ग्राम होड़ी दौड़ (कैनो रेस) चैम्पियनशिप 2026 का सफल आयोजन आज कार निकोबार के चुकचुचा गांव में किया गया। इस आयोजन में निकोबारी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं खेल परंपराओं की झलक देखने को मिली, जिसमें ग्रामीणों एवं प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार (आईएएस) ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा अत्यंत उत्साह एवं सामुदायिक भावना के बीच प्रतियोगिता के सेमीफाइनल एवं फाइनल चरण का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री अमित काले (आईएएस), उपायुक्त, निकोबार ज़िला, श्री राहुल एल. नायर (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक (ज़िला) तथा डॉ. नवीन कुमार, सहायक आयुक्त (मुख्यालय)/पीओ (आईटीडीपी) भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के उपरांत कार निकोबार के ग्रामीणों, जनजातीय परिषद के सदस्यों एवं विभिन्न कार्यालयों/विभागों के प्रमुखों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान स्थानीय समुदाय द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों एवं शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित सभी विभागों को निदेश दिया कि वे उपायुक्त, निकोबार ज़िला के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इन समस्याओं का समयबद्ध

एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। निकोबार ज़िले में जनजातीय समुदायों के विकास के उद्देश्य से, समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) के अंतर्गत मुख्य सचिव ने जनजातीय परिषद, कार निकोबार (सीटीसी) के अध्यक्ष को 100 पुस्तकें भेंट कीं। यह पहल जनजातीय समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा ज्ञान–विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई।

यह कार्यक्रम द्वीप प्रशासन की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाने तथा शैक्षणिक विकास को आगे बढ़ाने की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रंगत में दो दिवसीय बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल सम्पन्न

रंगत, 19 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वर्ष 2025–2026 के कार्यक्रम कैलेंडर के अंतर्गत 18 एवं 19 अप्रैल, 2026 को रंगत के निम्बूतला स्थित रमन बगीचा समुद्र तट पर दो दिवसीय बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा सहायक आयुक्त, मिडिल अंडमान कार्यालय, ग्राम पंचायत निम्बूतला तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से किया गया, जिसमें स्थानीय समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली।

इस अवसर पर युवाओं एवं स्थानीय निवासियों में शारीरिक फिटनेस, खेल भावना एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न बीच

खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में बीच वॉलीबॉल, 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी, बीच कबड्डी, बीच फुटबॉल तथा रस्साकशी जैसे खेल पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों के लिए आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, महिला प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से म्यूजिकल चेयर जैसी मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे पूरे आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। कार्यक्रम का समापन आज रमन बगीचा समुद्र तट पर आयोजित समापन समारोह के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री दीपांशु वोहरा, सहायक आयुक्त, मिडिल अण्डमान उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। समारोह के दौरान विजेताओं एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

रोचक समाचार के लिए पढ़िए
द्वीप समाचार

अंडर–17 राज्य स्तरीय लीग–कम–नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट

श्री विजय पुरम, 19 अप्रैल

अंडर–17 बालक एवं बालिका वर्ग के लिए आयोजित 8वीं राज्य स्तरीय लीग–कम–नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत आज खेले गए सेमीफाइनल मैचों के परिणाम घोषित किए गए।

अंडर–17 (बालक वर्ग)	
प्रथम सेमीफाइनल	ननकौड़ी ने डिगलीपुर को 07–00 से पराजित किया।
द्वितीय सेमीफाइनल	कार निकोबार ने कैंपबेल बे को 01–00 से हराया।
अंडर–17 (बालिका वर्ग)	
प्रथम सेमीफाइनल	श्री विजय पुरम ने डिगलीपुर को 12–00 से पराजित किया।
द्वितीय सेमीफाइनल	ननकौड़ी ने कार निकोबार को 05–03 से हराया।
लूज़र फाइनल (तीसरे स्थान का मैच) एवं फाइनल मुकाबले 20 अप्रैल, 2026 को नेताजी स्टेडियम में खेले जाएंगे।	
कल (20 अप्रैल, 2026) के मैचों की समय–सारणी	
लूजर फाइनल (तीसरे स्थान का मैच)	
अंडर–17 (बालिका वर्ग)	कार निकोबार बनाम डिगलीपुर, प्रातः 6 बजे–नेताजी स्टेडियम
अंडर–17 (बालक वर्ग)	कैंपबेल बे बनाम डिगलीपुर, प्रातः 7.30 बजे–नेताजी स्टेडियम
फाइनल मैच	
अंडर–17 (बालिका वर्ग)	श्री विजय पुरम बनाम ननकौड़ी, शाम 3 बजे–नेताजी स्टेडियम
अंडर–17 (बालक वर्ग)	कार निकोबार बनाम ननकौड़ी, सुबह 5 बजे–नेताजी स्टेडियम
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सभी फुटबॉल प्रेमियों से अनुरोध किया गया है कि वे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर द्वीपों के युवा एवं उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें।	

स्वच्छता कर्मियों हेतु समेकित स्वास्थ्य शिविर आयोजित

श्री विजय पुरम, 19 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसायटी (एएनएसीएस) द्वारा गाराचरामा स्थित प्रधान कार्यालय के सामुदायिक भवन में एक समेकित स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर स्वच्छता कर्मियों के लाभ के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन एएनएसीएस के परियोजना निदेशक डॉ. सुब्रत साहा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना तथा प्रतिभागियों को आवश्यक चिकित्सीय जांच सेवाएं उपलब्ध कराना था। इस पहल से कुल 25 स्वच्छता कर्मियों को लाभ मिला।

शिविर के दौरान प्रतिभागियों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जांच की गईं, जिनमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, रक्तचाप (बीपी), ब्लड शुगर स्तर तथा सिफिलिस शामिल थे। यह अभियान प्रारंभिक पहचान, रोकथाम एवं जागरूकता पर केंद्रित रहा।

एएनएसीएस द्वारा जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें नियमित स्वास्थ्य जांच, सुरक्षित व्यवहार एवं समय पर उपचार के महत्व पर जोर दिया गया। साथ ही प्रतिभागियों को अपने दैनिक जीवन में निवारक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

एएनएसीएस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि संस्था भविष्य में भी अन्य पंचायतों एवं वार्डों में कार्यरत कर्मचारियों के लाभ हेतु ऐसे समेकित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जारी रखेगी।

प्रदर्शनी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय

पृष्ठ 1 का शेष

शतरंज प्रतियोगिता के विजेता	
बालक वर्ग	बालिका वर्ग
प्रथम–रुशील	प्रथम–चार्वी डी.
द्वितीय–ईशान एस.	द्वितीय–नंदिनी
तृतीय–हरिप्रसाद	तृतीय–अग्रता सिंह

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को स्मृति–चिह्न प्रदान किए गए, जबकि स्टॉल विक्रेताओं को प्रमाण–पत्र वितरित किए गए।

अल्पसंख्यक कार्य तथा मत्स्य, पशुपालन

पृष्ठ 1 का शेष

विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में देश के कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अत्यधिक अधिक है, कुछ क्षेत्रों में यह संख्या 25 लाख से भी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जनता के साथ प्रभावी संवाद और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। इसलिए परिसीमन का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों के आकार को संतुलित करना, प्रशासनिक पहुंच को आसान बनाना और नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

मंत्री ने आगे कहा कि परिसीमन से अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि भविष्य में यहां सांसद की सीटों की संख्या एक से बढ़कर दो हो सकती है, जिससे क्षेत्र के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व और अपनी बात रखने का बेहतर अवसर मिलेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए श्री कुरियन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इस विधेयक का व्यक्तिगत श्रेय नहीं चाहते, बल्कि सभी दल मिलकर महिलाओं के अधिकारों के लिए इस महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुधार लंबे समय से लंबित था और अब इसे लागू करना समय की मांग है।

श्री कुरियन ने 1970 के दशक में अपनाए गए कुछ पुराने विधायी दृष्टिकोणों का भी उल्लेख किया और कहा कि उस समय बनाए गए कानून महिलाओं और वंचित वर्गों की समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं कर पाए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार इन कमियों को दूर करने और महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अंत में, मंत्री ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। उन्होंने दोहराया कि महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान देना देश की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी, राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती शीला सिंह सहित भाजपा के कई महिला नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का समर्थन किया।

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल प्रतिभागियों

पृष्ठ 1 का शेष

अक्सर उन्हें पारंपरिक कोचिंग सहायता नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, सूचना की उपलब्धता और स्व–अध्ययन उपकरणों के प्रसार ने पारंपरिक प्रणालियों पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है।

परीक्षा परिदृश्य में व्यापक बदलावों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि क्षेत्र, लैंगिक और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि – इन तीन आयामों में स्पष्ट बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों और विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमियों के उम्मीदवार अब शीर्ष रैंक हासिल कर रहे हैं, जो एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि प्रणाली को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री महोदय ने अपनी योग्यता को पहचानने और उसे करियर विकल्पों के साथ जोड़ने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे सुधारों ने विद्यार्थियों को मजबूरी के बजाय रुचि और क्षमता के आधार पर विषयों का अध्ययन करने के लिए सुगमता और स्वतंत्रता प्रदान की है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकारी पहलों पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभा सेतु मंच का जिक्र किया, जो साक्षात्कार चरण तक पहुंचने वाले लेकिन अंतिम चयन में शामिल न हो पाने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संभावित नियोक्ताओं से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिभा व्यर्थ न जाए और उत्पादक रूप से योगदान देती रहे।

ओडिशा में भारत की पहली उन्नत 3डी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास; एआई, 5जी और रक्षा तकनीक को बड़ा समर्थन

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

भारत के सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं और ओडिशा के भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी गंतव्य के रूप में उदय के एक निर्णायक क्षण में, देश की पहली उन्नत 3क चिप पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास आज इन्फो वैली, भुवनेश्वर में किया गया। यह परियोजना भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने और उच्च–स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को प्रतिबिंबित करती है।

हेटरोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस परियोजना, जिसे 3डी ग्लास सॉल्यूशंस समर्थन दे रहा है, का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी और रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में किया गया। इस परियोजना के शुभारंभ के साथ, ओडिशा दुनिया की सबसे उन्नत चिप पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों में से एक बन जाएगा।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री मोहन चरन माझी ने इस परियोजना को ओडिशा और देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार, एक उन्नत 3डी ग्लास सॉल्यूशंस सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित की जा रही है, जो राज्य के लिए अत्यधिक गर्व की बात है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी की विश्व–स्तरीय अग्रणी कंपनियां जैसे इंटेल, लॉकहीड मार्टिन, और एप्लाइड मैटेरियल्स अत्याधुनिक पैकेजिंग तकनीकों से जुड़ी हुई हैं और ओडिशा में उनकी रुचि राज्य की बढ़ती औद्योगिक शक्ति को प्रतिबिंबित करती है।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि राज्य में निर्मित उत्पाद अगली पीढ़ी के क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, और उन्नत डिजिटल प्रणालियाँ का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, ओडिशा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

श्री माझी ने जानकारी दी कि कंपनी इस परियोजना में लगभग 2,000 करोड़ निवेश कर रही है और इस सुविधा–केंद्र से प्रति वर्ष 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन असेंबल किए गए यूनिट और लगभग 13,000 उन्नत 3डीएचआई मॉड्यूल का उत्पादन होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और पहली 3क ग्लास सब्सट्रेट पैकेजिंग सुविधा स्थापित की जा रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा में बढ़ता सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम; इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और आईटीआई छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा, जिससे राज्य को संसाधन–आधारित अर्थव्यवस्था से तकनीक–आधारित विकास केंद्र में बदलने में मदद मिलेगी।

सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए ओडिशा के लोगों को बधाई दी और राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और इस बदलाव में ओडिशा एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है।

श्री वैष्णव ने कहा कि ओडिशा, जो पारंपरिक रूप से खनिजों, धातुओं और ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे उन्नत क्षेत्रों में भी धीरे–धीरे अपनी जगह बना रहा है। इस परियोजना को अपनी तरह की सबसे उन्नत विनिर्माण पहलों में से एक बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह भारत की सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला को काफी मजबूत करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में इस क्षेत्र में उत्पादन छह गुना बढ़ गया है। उन्होंने आगे कहा, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है और 2025 में मोबाइल फोन के अग्रणी निर्यातक के रूप में उभरा है।

विद्यालयों में नशा उन्मूलन, साइबर सुरक्षा, यातायात नियम एवं पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता अभियान

श्री विजय पुरम, 19 अप्रैल

दक्षिण अण्डमान जिला पुलिस द्वारा दक्षिण अण्डमान जिले के विभिन्न विद्यालयों में सफलतापूर्वक जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में नशा दुरुपयोग, साइबर अपराध, यातायात नियमों तथा पॉक्सो अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

6 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2026 के दौरान, दक्षिण अण्डमान जिला पुलिस के थाना प्रभारी (एसएचओ) एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कुल आठ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन एंटी–नारकोटिक्स सेल, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस कला मंच तथा प्रयास एनजीओ के सहयोग से किया गया, जिससे विद्यार्थियों तक प्रभावी एवं रोचक तरीके से संदेश पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम 6 अप्रैल, 2026 को राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भातूबस्ती में, 10 अप्रैल, 2026 को राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बम्बूफ्लाट में, 13 अप्रैल, 2026 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मंगलूटान में, 16 अप्रैल, 2026 को केवी–2, एनसीएस तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हैडो में तथा 18 अप्रैल, 2026 को निर्मला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए गए।

इन सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था, जिसमें इसके शारीरिक एवं कानूनी परिणामों पर विशेष प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों को ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े बढ़ते खतरों, जैसे साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी एवं डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति भी संवेदनशील बनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, गोपनीयता की सुरक्षा तथा सोशल मीडिया के सही उपयोग के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व तथा लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनी ढांचे की जानकारी दी तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में बिना भय के रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस कला मंच की भागीदारी ने कार्यक्रम में रचनात्मकता का समावेश किया, जहां प्रस्तुतियों एवं नाट्य प्रस्तुति (रोल–प्ले) के माध्यम से मुख्य संदेशों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। दक्षिण अण्डमान जिला पुलिस ने विद्यालय प्रशासन एवं विद्यार्थियों के उत्साहपूर्ण सहभागिता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। विभाग भविष्य में भी ऐसे जन–जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं को उनके अधिकारों, कानूनी व्यवस्था एवं समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समुचित जानकारी मिल सके।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) बिजू एस. पिल्लै
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

पोस्ट ऑफिस बीमा योजनाः ये है पोस्ट ऑफिस का 100 साल पुराना प्लान, मिलेगा 50 लाख तक बीमा कवर

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

अगर आप भी बीमा कराने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीमा योजनाओं के बढ़ते बाजार में जहां निजी कंपनियां ऊंचे प्रीमियम पर सीमित लाभ दे रही हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस की बीमा योजना अपने जबरदस्त बोनस और भरोसेमंद सुविधाओं के कारण आम जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। खासकर बोनस की दर इतनी आकर्षक है कि यह योजना अन्य बीमा कंपनियों से काफी आगे निकल जाती है।

इनमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भारत की सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस सर्विस है, जो 100 साल से भी अधिक समय से परिवारों को सुरक्षा कवरेज दे रही है। PLI में 19 साल की उम्र से ही शामिल होकर आप 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर ले सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें हर आयु और जरूरत के हिसाब से पॉलिसी उपलब्ध हैं, जो सुरक्षा के साथ–साथ बोनस और टैक्स लाभ भी देती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भारत की सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसे 1 फरवरी 1984 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में ये स्कीम सिर्फ पोस्टल एम्प्लॉयी के लिए थी। फिर 1888 में टेलीग्रॉफ डिपार्टमेंट में भी इसे चालू किया गया। फिर सेमी गर्वनमेंट वालें भी इसके दायरे में आ गए।

अब इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। अब ये ग्रामीण इलाकों तक किसान–मजदूरों तक के लिए भी उपलब्ध है। इंडिया पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इस स्कीम को ऑपरेट करता है। PLI ने ही तत्कालीन P-T डिपार्टमेंट की महिला कर्मचारियों को 1894 में कवर देना शुरू किया है। उस समय कोई कंपनी महिला कर्मचारियों को लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं देती थी।

युगल सुरक्षा प्लान– पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) की युगल सुरक्षा (Yugal Suraksha) पॉलिसी शादीशुदा जोड़ों के लिए खास है। इस पॉलिसी के तहत पति–पत्नी दोनों एक ही कवर के तहत सुरक्षित रहते हैं। बोनस सहित भुगतान जीवनसाथी को या पॉलिसी मैच्योर होने पर मिलता है, जिससे जोड़ों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित बनता है।

युगल सुरक्षा प्लान की खास बातें

स्कीम का फायदा लेने के लिए कपल की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।

सीनियर पॉलिसी होल्डर की मैक्सिमम एज 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

पॉलिसी का मिनिमम टेन्योर 5 साल और मैक्सिमम टेन्योर 20 साल होना चाहिए।

इस स्कीम में पति या पत्नी में कोई एक चस्प के पात्र होने चाहिए।

युगल सुरक्षा योजना में मिनिमम कवर 20000 होनी चाहिए।

मैक्सिमम कवर 50 लाख रुपये तय की गई है।

ये स्कीम कम प्रीमियम में ज्यादा बोनस देती है।

3 साल बाद इस पर लोन लिया जा सकता है।

चारधाम यात्रा : अब तक 19.52 लाख से अधिक पंजीकरण

देहरादून, 19 अप्रैल। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह व आस्था देखी जा रही है। इस साल चारधाम के लिए अब तक कुल 19.52 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने विभिन्न धामों के लिए पंजीकरण कराया हैं। रविवार शाम पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 6.80 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि बद्रीनाथ के लिए 5.75 लाख, गंगोत्री के लिए 3.43 लाख, यमुनोत्री के लिए 3.33 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए करीब 19 हजार पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। रविवार से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। यात्रा के शुरुआती दिनों में ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए 20 और 21 अप्रैल के लिए कुल 28,723 तीर्थयात्रियों का पंजीकरण कराया है।

इतिहास के पन्नों में 20 अप्रैल : क्रूरतम तानाशाह 'एडोल्फ हिटलर' का उदय

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

20 अप्रैल 1889 को जन्मे एडोल्फ हिटलर को दुनिया इतिहास के सबसे क्रूर और विनाशकारी तानाशाहों में गिना जाता है। उसके नेतृत्व में हुए निर्णयों और नीतियों ने दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयावह घटना की ओर धकेल दिया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई और वैश्विक स्तर पर भारी तबाही हुई।

पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद हिटलर ने 1918 में National Socialist German Workers* Party की स्थापना की, जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी कहा जाता है। उसने राष्ट्रवाद और उग्र भाषणों के सहारे बड़ी संख्या में लोगों को अपने पक्ष में किया और धीरे–धीरे जर्मनी की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।

हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया और समाज में उनके खिलाफ गहरी नफरत फैलाने की नीति अपनाई। इसके परिणामस्वरूप इतिहास के सबसे दर्दनाक नरसंहारों में से एक हुआ, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की विस्तारवादी नीतियों ने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। यह युद्ध इतिहास का सबसे घातक संघर्ष माना जाता है, जिसमें करोड़ों लोग प्रभावित हुए।

रिपोर्टों के अनुसार, जब रूसी सेनाएं बर्लिन के करीब पहुंच गईं, तो हिटलर ने 1945 में बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर ली। हालांकि इतिहास में उसके जन्मदिन को किसी आधिकारिक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन कुछ देशों में उसकी विचारधारा और गतिविधियों को लेकर अलग–अलग संदर्भों में चर्चाएं होती रही हैं। हिटलर का जीवन आज भी दुनिया के लिए एक चेतावनी माना जाता है कि उग्रवाद, नफरत और तानाशाही विचारधाराएं मानवता के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती हैं।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र– 1777 – न्यूयॉर्क ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना नया संविधान अपनाया था। यह अमेरिक स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था।

1902 – मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने पिचब्लेंड खनिज से रेडियोएक्टिव पदार्थ रेडियम और पोलोनियम को अलग करने में सफलता हासिल की थी।

1946 – संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशन्स भंग की गई।

1953 – कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सेना के बीच बीमार युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ था।

1972 – अपोलो 16 अभियान छह घंटों तक संकट से जूझने के बाद चंद्रमा पर उतर गया। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चांद पर उतरने वाली इतिहास की पांचवीं टीम बनी।

1997 – इंद्र कुमार गुजराल देश के 12वें प्रधानमंत्री बने।

1999 – जर्मन के पूर्व चांसलर हेल्मुट कोल अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ़्रीडम' से सम्मानित।

1999 – अमेरिका के कोलोराडो राज्य के लिटिलटन में कोलंबाइन हाई स्कूल में दो छात्रों ने गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 12 छात्रों और एक शिक्षक की मौत हो गई। बाद में घटना को अंजाम देने वाले दोनों छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

2006 – भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की।

2008 – अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नौ दिन बिताने के बाद पहला दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष यात्री यीसोयओन पृथ्वी पर सकुशल लौटे।

नेपाल के मुस्तांग जिले में लाल पहाड़ी के भीतर मिला 1200 वर्ष पुराना रहस्यमयी गुफा

काठमांडू, 19 अप्रैल।

नेपाल के मुस्तांग जिले के वारागुंग मुक्तिक्षेत्र के छुसॉन्ग में लाल मिट्टी के पहाड़ की दीवार को काटकर बनाई गई गुफाओं के भीतर भी एक गुम्बा (बौद्ध मठ) स्थित है। इस गुम्बा में स्थापित मूर्तियों के इतिहास को समझने पर पता चलता है कि गुफा के अंदर स्थित यह गुम्बा लगभग 1,200 वर्ष से भी अधिक पुराना है।

जोमसोम होते हुए कागबेनी–कोरला सड़क के पास एक खड़ी ढलान पर स्थित इस गुफा के भीतर के गुम्बा को 'मिन्ची ल्हवंग' गुम्बा कहा जाता है। यह धार्मिक बौद्ध गुम्बा छुसॉन्ग गांव के छह परिवारों के स्वामित्व में है। यहां प्रतिदिन शाम को इन छह परिवारों के सदस्य बारी–बारी से दीप जलाते हैं और पूजा–अर्चना करते हैं।

कोरला सड़क मार्ग के ऊपर खड़ी ढलान पर स्थित यह गुफा अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थान पर है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्राचीन काल में छुसॉन्ग गांव के पूर्वजों ने पहाड़ को काटकर यहां गुम्बा स्थापित किया था। यह गुम्बा वास्तव में कितने वर्ष पुराना है, इसका विवरण वर्तमान पीढ़ी के पास भी नहीं है। प्राचीन काल में मनांग से आए पूर्वज अपने देवता को साथ लेकर छुसॉन्ग गांव में बस गए थे।

स्थानीय निवासी श्याम गुरूंग ने बताया कि कमजोर भौगोलिक संरचना में स्थित यह गुफा स्वयं में जोखिमपूर्ण है। इसके पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी इन छह परिवारों पर है। उनके अनुसार पीढ़ियों से ये परिवार गुफा और गुम्बा की देखभाल करते आ रहे हैं।

करीब 100 मीटर ऊंचे मिट्टी के पहाड़ में स्थित इस गुफा को भूस्खलन और बाढ़ से नुकसान पहुंचने का खतरा है, इसलिए संबंधित निकायों को इसके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। इस पर स्थानीय गुरूंग परिवार ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक भगवान की कृपा से गुफा और गुम्बा को कोई क्षति नहीं हुई है।

इस अनोखी गुफा के ऊपरी तल पर गुम्बा स्थापित है। गुम्बा में मिट्टी से बनी बुद्ध की विभिन्न मूर्तियां हैं, जो 800 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जाती हैं। एक फ्रेम में रखी हरितारा की पत्थर की मूर्ति को लगभग 1,200 वर्ष पुरानी माना जाता है। मिन्ची ल्हवंग गुम्बा की गुफा के अंदर वर्षों पुराने कलात्मक चित्र भी मौजूद हैं। गुफा के भूगोल के अनुरूप मिट्टी के रंगों से ऊपरी तल की दीवारों और छत पर चित्रकारी की गई है।

स्थानीय गुरूंग के अनुसार गुफा के दूसरे तल के एक कोने में बुद्ध की मूर्तियां रखी गई हैं और वहां परिक्रमा करने की भी व्यवस्था है। इस गुफा और गुम्बा पर कुछ विदेशी शोधकर्ताओं ने भी अध्ययन किया है। संरक्षण के लिए विदेशी संस्थाओं ने तकनीकी और आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया है। छुसॉन्ग की ढलान पर स्थित इस गुफा में पहले और दूसरे तल पर रोशनी के लिए खिड़की जैसे छोटे छेद बनाए गए हैं। गुफा के भूतल से ऊपर जाने के लिए दो लकड़ी की सीढ़ियां हैं, जिनके सहारे ऊपर के तल तक पहुंचा जा सकता है।

विरासत और बुद्धिमत्ता का संगमः एआई के जरिए कारीगरों का सशक्तिकरण

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

समावेशी डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2,500 से अधिक लाभार्थियों– जिनमें पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार शामिल है– को अपनी आजीविका और व्यावसायिक संभावनाओं को बेहतर बनाने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपकरणों का उपयोग करने के संबंध में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।

यह पहल "सामाजिक कल्याण हेतु एआई" की परिकल्पना के अनुरूप है। माननीय प्रधानमंत्री ने इंडियाएआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इस परिकल्पना पर जोर दिया था और यह दिल्ली घोषणापत्र में भी परिलक्षित होती है। यह भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा किया गया अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर के कारीगरों को तेजी से विकसित हो रहे एआई इकोसिस्टम में एकीकृत करना है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावहारिक एवं प्रायोगिक सत्रों के जरिए आयोजित किया गया। इसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया, ताकि विभिन्न व्यवसायों के कारीगरों के लिए इसकी सुलभता एवं प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके।

प्रतिभागियों को चैटजीपीटी, इंडस और गूगल जेमिनी जैसे प्रमुख एआई प्लेटफॉर्म से परिचित कराया गया, ताकि वे वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें।

इस प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों को व्यावहारिक एआई–आधारित कौशल से सशक्त बनाना था, जिनमें शामिल हैं:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से परिचय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एआई उपकरणों का संक्षिप्त विवरण

ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग और विपणन संबंधी रणनीतियां

डिजिटल और एआई–आधारित उपायों का उपयोग करके व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना

ग्राहकों के साथ जुड़ाव और बाजार के पहुंच के विस्तार हेतु एआई का लाभ उठाना

'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल': पहलवान गीता फोगाट और मुक्केबाज स्वीटी बूरा ने महिलाओं की भागीदारी को सराहा

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने वाली प्रतिभागियों में खेल और मनोरंजन जगत के कई बड़े नाम भी शामिल थे। खेल जगत से पहलवान गीता फोगाट, मुक्केबाज स्वीटी बूरा, जूडो खिलाड़ी प्रिया शर्मा, अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी, अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन शामिल हुए।

इस मौके पर आईएएनएस से बात करते हुए गीता फोगाट ने कहा, "यह एक खास दिन था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सबमें बहुत ऊर्जा थी। हमारे प्रधानमंत्री ने 6–7 साल पहले यह पहल शुरू की थी। उस समय से लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ी है।"

आईएएनएस से बात करते हुए स्वीटी बूरा ने कहा, "मुझे बहुत अच्छा लगा। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैं पहले भी 'संडे ऑन साइकिल' में आई थी, लेकिन उस समय इतना जोश नहीं था। इतने सारे कार्यक्रम और महिलाओं में फैली जागरूकता की वजह से अब महिलाओं की भागीदारी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।"

प्रिया शर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं यहां पहली बार आई हूं। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि यहां इतना बड़ा इवेंट होता है, और इतनी सारी महिलाएं यहां आती हैं। मुझे खुशी है कि यहां महिलाओं के लिए कुछ खास आयोजित किया गया।"

अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। महिलाओं का हर कोने, हर राज्य और हर शहर से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसी पहल बहुत खास होती हैं।"

साइकिल रैली में महिला प्रतिभागियों के साथ मिलिंद सोमन भी शामिल हुए। मिलिंद ने महिला प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाई और अन्य फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हुए। इस दौरान अधिकांश महिला प्रतिभागी गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थीं। मिलिंद सोमन ने कई महिलाओं को पुरस्कृत भी किया।

'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' का आयोजन प्रत्येक रविवार को देश के अनेक हिस्सों में किया जाता है। केंद्र सरकार के युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस इवेंट का उद्देश्य देशवासियों, खासकर युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता को बढ़ाना है। युवाओं में बढ़ रही मोटापे की समस्या को कम करने के लिए भी साइक्लिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साइक्लिंग पर्यावरण के बेहतर बनाए रखने की दिशा में भी अहम है।

लीवर–मौन प्रहरी जो हर पल बचाता है आपका जीवन

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

मानव शरीर प्रकृति की एक अद्वितीय कृति है, जिसमें प्रत्येक अंग अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हुए जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। इस जटिल तंत्र में लीवर (यकृत) का स्थान अत्यंत केंद्रीय है। यह न केवल शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है, बल्कि अपने बहुआयामी कार्यों के कारण जीवन–चक्र का मौन संचालक भी है। इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने इस अनमोल अंग के प्रति जागरूक होने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।

लीवर वास्तव में शरीर की 'रासायनिक प्रयोगशाला' है, जहां 500 से अधिक जैव–रासायनिक प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। यह भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है, पित्त का निर्माण करता है, रक्त को शुद्ध करता है और आवश्यक प्रोटीन व एंजाइम का उत्पादन करता है। सरल शब्दों में, यह शरीर के भीतर एक सतर्क प्रहरी की तरह हर क्षण स्वास्थ्य की रक्षा करता है।

लीवरः शरीर का पावर हाउस– लीवर पेट के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होता है और इसका वजन लगभग 1.3–1.5 किलोग्राम होता है। इसे 'पावर हाउस' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा, पाचन और शुद्धिकरण प्रणाली का केंद्र है। इसकी सबसे विलक्षण विशेषता इसकी पुनर्जीवन क्षमता है। यदि इसका बड़ा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो जाए, तो यह स्वयं को पुनः विकसित कर सकता है। यही गुण इसे अन्य अंगों से अलग और अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।

शराब लीवर के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि इसका प्रसंस्करण सीधे लीवर में होता है। यह एसीटैल्डिहाइड जैसे विषैले पदार्थ बनाकर लीवर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। लगातार शराब पीने से फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और अंततः सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शुरुआत में लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन धीरे–धीरे लीवर की कार्यक्षमता कम होती जाती है। एक बार सिरोसिस हो जाने पर स्थिति को पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं होता। इसलिए सबसे सुरक्षित उपाय शराब से दूरी बनाना है।

आधुनिक जीवनशैली और संक्रमण के कारण लीवर से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। 1. फैटी लीवर– लीवर में अत्यधिक वसा जमा होने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। मोटापा, मधुमेह, खराब खान–पान और निष्क्रिय जीवनशैली इसके मुख्य कारण हैं। 2. हेपेटाइटिस–यह लीवर की सूजन है, जो मुख्यतः वायरस (A, B, C, D,E) के कारण होती है। हेपेटाइटिस B और C लंबे समय में गंभीर रूप ले सकते हैं। 3. सिरोसिस– यह एक अपरिवर्तनीय अवस्था है, जिसमें लीवर की कोशिकाएं नष्ट होकर स्कार टिश्यू में बदल जाती हैं। शराब और क्रोनिक संक्रमण इसके प्रमुख कारण हैं। 4. लीवर कैंसर– यह अक्सर सिरोसिस या लंबे समय के हेपेटाइटिस संक्रमण के बाद विकसित होता है और प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते।

आज की जीवनशैली लीवर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अल्ट्रा–प्रोसेस्ड फूड और फ्रुक्टोजः सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड लीवर में वसा बढ़ाते हैं। मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोमः इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण फैटी लीवर का खतरा। दवाओं का अति–प्रयोगः विशेषकर पैरासिटामोल का ओवरडोज खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं।

लीवर की बीमारियां अक्सर 'मूक' होती हैं, लेकिन कुछ संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक लक्षण–लगातार थकान। भूख में कमी। मतली या उल्टी। पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन। गंभीर लक्षण–पीलिया (त्वचा/आंखों का पीला पड़ना)।पेट में सूजन (एसाइटिस) पैरों में सूजन। गहरे रंग का मूत्र और फीका मल। मानसिक भ्रम (हेपेटिक एन्सेफैलोपैथी) ये खराब लीवर के मूल लक्षण हैं।

लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन शैली में सुधार सबसे प्रभावी उपाय है। संतुलित आहारः फल, सब्जियां, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। नियमित व्यायामः सप्ताह में कम से कम 150 मिनट। वजन नियंत्रणः 7–10% वजन घटाना भी लाभकारी। शराब और दवाओं से सावधानी। टीकाकरणः हेपेटाइटिस A और B से बचाव।नियमित जांचः LFT, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन। आदि जांच से समय रहते बीमारी की गंभीरता का पता लगाया जा सकता है।

हेपेटोलॉजी में तेजी से प्रगति ने उपचार को अधिक प्रभावी बना दिया है। हेपेटाइटिस C का इलाजः नई दवाओं से 95% तक सफलता। नॉन–इनवेसिव जांचः फाइब्रोस्कैन और MRI तकनीक। लीवर ट्रांसप्लांटः बढ़ती सफलता दर और लिविंग डोनर विकल्प। स्टेम सेल थेरेपीः भविष्य की एक आशाजनक संभावना के रूप में उभर रही है।

लीवर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित जीवन शैली सबसे जरूरी है। अपने आहार में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर शामिल करें, जबकि तला–भुना, मीठा और प्रोसेस्ड भोजन सीमित रखें। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट नियमित व्यायाम करें और वजन नियंत्रित रखें, इससे लीवर में वसा जमाव कम होता है। शराब से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह लीवर को सीधा नुकसान पहुंचाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन न करें, खासकर दर्द निवारक दवाओं का। हेपेटाइटिस A और B का टीकाकरण करवाना और स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी है। समय–समय पर लीवर की जांच कराते रहें, ताकि किसी समस्या का समय रहते पता चल सके।

मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए डिजाइन किए गए जी–20 उपग्रह को 2027 में किया जाएगा प्रक्षेपितः इसरो अध्यक्ष

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने शनिवार को कहा कि जलवायु, वायु प्रदूषण का अध्ययन करने और मौसम की निगरानी करने के लिए डिजाइन किए गए जी20 उपग्रह को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में डीआरडीओ, इसरो और एयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए डॉ. नारायणन ने यह भी कहा कि भारत पहला देश है जिसने बिना किसी टक्कर के एक ही रॉकेट का उपयोग करके 100 से अधिक उपग्रहों सहित 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

उन्होंने कहा, "फिलहाल हम जी–20 देशों के लिए एक जी–20 उपग्रह पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और हम 2027 तक इसका प्रक्षेपण करने जा रहे हैं।" आईएसआरओ प्रमुख ने आगे कहा कि कई वाणिज्यिक मिशनों को अंजाम दिया गया, जिनमें 34 देशों के 433 उपग्रह शामिल हैं, और भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह भी एक वाणिज्यिक उपग्रह था।

नारायणन ने कहा कि इसरो 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "अगर हम 2040 तक इसे हासिल कर लेते हैं, तो हम लॉन्चर प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग क्षेत्र और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के मामले में किसी भी अन्य अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के बराबर होंगे। और हम विकसित भारत–2024 की दिशा में काम कर रहे हैं।"

उनके अनुसार, इसरो डीप ओशन मिशन के एक प्रोजेक्ट, समुद्रयान के लिए 2.2 मीटर व्यास और 100 मिलीमीटर मोटाई वाला टाइटेनियम का एक पोत बनाने की प्रक्रिया में है।

देश में ईंधन आपूर्ति सामान्य, भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार सतर्क

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर केंद्र सरकार ने बताया कि तेल आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बावजूद देश में तेल और गैस आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, बंदरगाहों का संचालन सामान्य है और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षित वापसी तथा सहायता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार मौजूदा भू–राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें। एलपीजी उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से बुकिंग करने और वितरकों के पास अनावश्यक भीड़ न लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही, पीएनजी, इलेक्ट्रिक या इंडक्शन जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा की बचत करने का आग्रह किया गया है।

केंद्र ने कहा कि रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर संचालित हो रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है और किसी भी वितरण केंद्र पर गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। 17 अप्रैल को 52 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। वहीं, 23 मार्च से अब तक 5 किलोग्राम के 17.25 लाख से अधिक एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, दवा, स्टील, ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता दी गई है। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम सिलेंडरों की उपलब्धता दोगुनी कर दी गई है।

वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को संकट पूर्व स्तर के लगभग 70 प्रतिशत तक बहाल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा ऑटो एलपीजी की बिक्री में 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पीएनजी विस्तार सुधारों से जुड़े अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन दिए जा रहे हैं। सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए भी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं, जिससे एलपीजी पर दबाव कम किया जा सके।

आपूर्ति और मांग के संतुलन के लिए बुकिंग अंतराल को शहरी क्षेत्रों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक किया गया है। साथ ही केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई के लिए सशक्त किया गया है। 17 अप्रैल को देशभर में 2500 से अधिक छापे मारे गए, जिनमें 750 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए। तेल विपणन कंपनियों ने 263 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया और 67 को निलंबित किया है।

स्मार्टफोन्स में प्री–इंस्टॉल नहीं होगा आधार ऐप

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

स्मार्टफोन यूजर्स और मोबाइल कंपनियों के लिए एक अहम खबर है। भारत सरकार ने स्मार्टफोन्स में आधार ऐप को अनिवार्य रूप से प्री–इंस्टॉल करने के अपने प्रस्ताव को अब आधिकारिक तौर पर वापस लेने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब एप्पल, सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन कंपनियों को भारत में बिकने वाले अपने मोबाइल फोन्स में पहले से आधार ऐप डालकर देने की कोई जरूरत नहीं होगी। दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियों के भारी विरोध के बाद एक सरकारी संस्था ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार अब इस प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं करेगी।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आधार का संचालन करने वाली सरकारी संस्था यूआईडीएआई (UIDAI) ने इसी साल जनवरी में आईटी मंत्रालय से संपर्क साधा था। यूआईडीएआई ने मंत्रालय से एप्पल, गूगल और अन्य प्रमुख स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ बातचीत कर आधार ऐप को फोन में प्री–इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने की मांग की थी।

हालांकि, अब UIDAI ने अपने एक बयान में स्पष्ट कर दिया है कि आईटी मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की गहन समीक्षा की है और वह स्मार्टफोन पर इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। गौरतलब है कि देश के करीब 1.34 अरब लोगों के पास 12 अंकों का यह यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग से लेकर एयरपोर्ट पर फास्ट एंट्री तक में किया जाता है। UIDAI का कहना है कि आईटी मंत्रालय ने इस आधार प्री–इंस्टॉलेशन प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्द करने का अंतिम फैसला लेने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तार से परामर्श किया था।

अंटार्कटिका के समंदर में दिखा नया द्वीप, कैसे बनते हैं नए टापू और आखिर कौन होगा इसका मालिक?

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

अंटार्कटिका की जमा देने वाली लहरों और विशाल बर्फ की चादरों के बीच प्रकृति अक्सर अपने रहस्य छुपाए रखती है। हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक दल ने कुछ ऐसा ही करिश्मा देखा है, जिसने पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है। अंटार्कटिका के वेडेल सागर में एक नए द्वीप की खोज की गई है, जो पहले कभी नक्शों पर दर्ज नहीं था।

अल्फ्रेड वेगनर संस्थान के विशेषज्ञ साइमन ड्रुटर बताते हैं कि उन्हें दूर से एक बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो वह बर्फ नहीं, बल्कि चट्टान थी। जैसे ही जहाज ने अपना रास्ता बदला और करीब गया, यह साफ हो गया कि उनके सामने एक नया द्वीप खड़ा था।

यह सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि क्या समुद्र के बीच से अचानक कोई जमीन का टुकड़ा बाहर आ सकता है? लेकिन आपको बता दें यह पूरी तरह मुमकिन है। द्वीप बनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट और भूगर्भीय हलचलों पर निर्भर करती है। ज्वालामुखी विस्फोट– जब समुद्र की गहराई में मौजूद ज्वालामुखी फटते हैं, तो उनसे निकलने वाला लावा पानी के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है। धीरे–धीरे यह जमाव समुद्र की सतह से ऊपर आ जाता है और एक द्वीप का रूप ले लेता है।

टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल– पृथ्वी के अंदर मौजूद प्लेटों के खिसकने से भी कभी–कभी नया भूभाग ऊपर की ओर उठ जाता है।

कोरल रीफ और डिप्रेशन– ट्रॉपिक क्षेत्रों में कोरल्स के अवशेषों या समुद्री धाराओं से जमा की गई रेत और मिट्टी से भी नए टापुओं का निर्माण होता है।

एक दिलचस्प सवाल यह उठता है कि क्या इस द्वीप को खोजने वाले वैज्ञानिक या उनका देश इस पर अपना कब्जा

जमा सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, इसका जवाब ना है। कानून कहता है कि अगर कोई नया द्वीप किसी देश की समुद्री सीमा के 200 समुद्री मील के भीतर बनता है, तो उस पर उसी निकटतम तटीय देश का संप्रभु अधिकार होता है।

खोजने वाले व्यक्ति का उस पर कोई मालिकाना हक नहीं होता। अगर कोई द्वीप किसी भी देश की सीमा से 200 मील दूर, यानी इंटरनेशनल वॉटर्स में बनता है, तो तकनीकी रूप से वह किसी का नहीं होता। उसे अपना देश घोषित करना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए दुनिया के अन्य देशों से मान्यता मिलना जरूरी है।

यह खोज एक इत्तेफाक और वैज्ञानिकों की सजगता का नतीजा है। 8 फरवरी 2026 से, जर्मन रिसर्च आइसब्रेकर पोलरस्टर्न पर सवार 93 सदस्यों का एक दल उत्तर–पश्चिमी वेडेल सागर की खोज कर रहा था। यह दल मुख्य रूप से समुद्री धाराओं और पिघलती बर्फ का अध्ययन करने के लिए वहां मौजूद था।

अचानक समुद्र में मौसम खराब हो गया और तेज लहरों से बचने के लिए जहाज को जॉइनविले द्वीप की आड़ में शरण लेनी पड़ी। इसी दौरान वैज्ञानिकों की नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी, जिसे समुद्री चार्ट पर केवल एक खतरे के क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने देश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जारी किए दिशा–निर्देश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षित सड़कें नागरिकों का मौलिक अधिकार हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर है।

यह सख्त रुख नवंबर 2025 में राजस्थान और तेलंगाना में हुए दो भीषण हादसों के बाद अपनाया गया, जिनमें 34 लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पूरे देश के लिए व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए।

अदालत के आदेश के मुताबिक, अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी वाहन खड़ा करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही रोके जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कैमरा और जीपीएस आधारित चालान प्रणाली लागू की जाएगी।

इसके साथ ही, हाईवे किनारे अवैध रूप से बने ढाबों, दुकानों और अन्य अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नए निर्माण कार्यों पर भी तत्काल रोक लगाने को कहा गया है। कोर्ट ने हर जिले में 'हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स' गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें प्रशासन, पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम नियमित निगरानी और सुरक्षा

व्यवस्था की समीक्षा करेगी।

आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने हर 75 किलोमीटर पर एंबुलेंस और क्रेन की तैनाती अनिवार्य की है। साथ ही, जिन स्थानों पर बार–बार हादसे होते हैं, यानी 'ब्लैकस्पॉट्स', उनकी पहचान कर वहां बेहतर रोशनी, सीसीटीवी कैमरे और चेतावनी संकेत लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि देश के कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों की हिस्सेदारी मात्र 2 प्रतिशत है, लेकिन यहां करीब 30 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अदालत ने सभी संबंधित एजेंसियों को 75 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है

मनरेगाः केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17,744 करोड़ रुपये जारी किए

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय वर्ष 2026–27 की पहली किस्त के रूप में, मजदूरी घटक की मद में 17,744.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इन फंड्स का समय पर और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल सुनिश्चित करें, ताकि मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जरूरी फंड्स, सामग्री और प्रशासनिक घटकों के तहत भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम जमीनी स्तर पर बिना किसी रुकावट के और लगातार चलते रहने चाहिए।

शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि मजदूरों को समय पर काम उपलब्ध कराना और मजदूरी का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्यों को सलाह दी गई कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर काम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी मजदूर को रोजगार के लिए इंतजार न करना पड़े। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार की मांग करने वाले हर मजदूर को तय समय सीमा के भीतर काम दिया जाना चाहिए, और सभी स्तरों पर मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम की जगहों के प्रभावी प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया और राज्यों से आग्रह किया कि वे उन योग्य ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने को प्राथमिकता दें, जिन्हें अभी तक इसके दायरे में नहीं लाया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इच्छुक परिवारों को एक तय समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी योग्य परिवार आजीविका के अवसरों से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय एक महत्वपूर्ण बदलाव का दौर है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार को बनाए रखना जरूरी है, और साथ ही वीबी–जी राम जी ऐक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी जरूरी तैयारियां भी पूरी करनी हैं।

वीबी–जी राम जी ऐक्ट के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देकर, एक दूरदर्शी और सशक्तिकरण–आधारित ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को संभव बनाने के लिए सभी प्रारंभिक कार्य एक तय समय सीमा के भीतर पूरे करें।

तीन आईसीसी ट्रॉफियां जिताने वाले अजीत अगरकर 2027 वर्ल्ड कप तक रहेंगे चीफ सेलेक्टर

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को उनके पद पर एक्सटेंशन मिलने की पूरी संभावना है। अगरकर का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में खत्म होने जा रहा है, लेकिन उनके शानदार कार्यकाल और टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड उन्हें आगे भी इस अहम जिम्मेदारी पर बनाए रखने के पूरे पक्ष में है। अगर यह फैसला आधिकारिक रूप लेता है, तो आगामी वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया की चयन नीति की कमान एक बार फिर अजीत अगरकर के हाथों में ही रहेगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की नजरें अब सीधे तौर पर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर टिक गई हैं। इसी मेगा इवेंट की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अजीत अगरकर को एक्सटेंशन देने का फैसला लगभग तय माना जा रहा है। बोर्ड का मानना है कि अगरकर की अगुवाई में चयन समिति ने बेहतरीन काम किया है और ऐसे में आगामी वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने की जिम्मेदारी के लिए उन पर ही भरोसा जताना सबसे सही कदम होगा। जुलाई 2023 में चीफ सेलेक्टर की कुर्सी संभालने वाले अगरकर के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का भी लंबा अनुभव है।

अजीत अगरकर के अब तक के कार्यकाल को बीसीसीआई

के गलियारों में बेहद सफल माना जा रहा है। उनके समय में टीम इंडिया ने लगातार बड़े टूर्नामेंट्स में अपना दबदबा कायम करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े खिताब लगातार अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगरकर के नेतृत्व में टीम इंडिया में बदलाव (ट्रांजिशन) का दौर काफी आसानी से गुजरा है। सीनियर और युवा खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन संतुलन बनाने के साथ–साथ उनके द्वारा सेलेक्शन में लिए गए साहसिक व निडर फैसलों ने भारतीय टीम को नई दिशा दी है।

गोवा की साध्वी सैल बनीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026

भुवनेश्वर, 19 अप्रैल।

भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण में गोवा की साध्वी सैल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार को फर्स्ट रनर–अप और अद्वैता को सेकेंड रनर–अप घोषित किया गया। प्रतियोगिता के नतीजों के साथ ही विजेताओं के नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए।

भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी यूनिवर्सिटी में आयोजित इस भव्य समारोह का थीम कनेक्टिंग द डॉट्स–डाल्टर्स ऑफ दिस सोयल रखा गया था। इस थीम के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को मंच पर खूबसूरती से पेश किया गया। देशभर से आई प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसने ग्रैंड फिनाले को यादगार बना दिया।

प्रतियोगिता की शुरुआत पिछले वर्ष नवंबर में देशभर में आयोजित टैलेंट हंट से हुई थी, जिसमें अलग–अलग राज्यों से प्रतिभागियों का चयन किया गया। इसके बाद टॉप 30 प्रतिभागियों ने मुंबई में विशेष ग्रूमिंग सेशन में हिस्सा लिया। ग्रैंड फिनाले से पहले प्रतिभागियों ने ओडिशा की संस्कृति को करीब से जाना और पुरी के जगन्नाथ

मंदिर व कोणार्क सूर्य मंदिर का दौरा भी किया।

इस रंगारंग शाम को मनीष पॉल और सारा जेन डायस ने होस्ट किया, जबकि जुबिन नौटियाल, लॉरेन गॉटलिब और ईशान खट्टर की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। जज पैनल में जीनत अमान, मधुर भंडारकर, दूती चंद, नेहा धूपिया, टेरेंस लुईस, सेलिना जेटली और अमाल मलिक जैसे कई प्रतिष्ठित नाम शामिल रहे। इस आयोजन ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय युवतियां सुंदरता के साथ आत्मविश्वास और उद्देश्य के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हैं।